परिचय

पब्लिक अफेयर्स सेंटर (PAC) भारत के संदर्भ में सतत विकास लक्ष्यों (SDG) पर ध्यान केंद्रित करते हुए अनुसंधानात्मक कार्रवाई में संलग्न है। पीएसी भारत में शासन की गुणवत्ता में सुधार के लिए, जनादेश के तहत **1994** में स्थापित एक गैर लाभकारी थिंक टैंक है।

पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स भारत के राज्यों में शासन की पर्याप्तता और गुणवत्ता का वार्षिक मूल्यांकन है। एक समग्र सूचकांक के आधार पर, राज्यों को शासनात्मक प्रदर्शन के आधार पर स्थान दिया जाता है। PAI **2021** एक गैर-पक्षपाती, स्वतंत्र और साक्ष्य-आधारित अध्ययन है जिसमें केवल सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध केंद्र सरकार के डेटा का उपयोग किया जाता है। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स की एक अनूठी विशेषता यह है कि, इस इंडेक्स की कम्प्यूटर आधारित गणना में व्यक्तिपरक पूर्वाग्रहों को स्थान नहीं दिया जाता, यानी इस प्रकार उत्पन्न परिणाम प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस (PCA) की वैज्ञानिक रूप से दृढ़ पद्धति का उपयोग करके कंप्यूटर द्वारा प्रदान किए जाते हैं।

पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021

PAI 2021, सतत विकास के संदर्भ में शासन के प्रदर्शन को तीन स्तंभों के आधार पर देखता है - इक्विटी, विकास और स्थिरता, पांच थीम, **14** एसडीजी और **43** संकेतक। स्तंभ-वार रैंकिंग और विश्लेषण के अलावा, **PAI 2021** में पांच केंद्र प्रायोजित योजनाओं-महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (**MGNREGS**), राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (**NHM**), एकीकृत बाल विकास सेवाओं (**ICDS**), समग्र शिक्षा अभियान (SmSA) और मध्याह्न भोजन योजना (MDMS) के कार्यान्वयन की प्रभावशीलता का आकलन भी शामिल है।

PAI 2021 की एक अन्य हाईलाईट **COVID-19** प्रतिक्रिया सूचकांक है - महामारी के लिए राज्यों की शासनात्मक प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण और इसके प्रभाव को कम करने में प्राप्त सफलता की डिग्री।

PAI 2021 शुक्रवार, **29** अक्टूबर, **2021** को बेंगलुरु में लॉन्च किया गया। यह भारत में राज्यों के शासनात्मक प्रदर्शन की रैंकिंग का लगातार छठा वर्ष है। **PAI 2021** के परिणाम इस प्रकार हैं:

PAI 2021 समग्र सूचकांक- स्कोर और रैंकिंग

बड़े राज्य	रैंक	**PAI 2021** सूचकांक स्कोर
केरल	1	1.618
तमिलनाडु	2	0.897
तेलंगाना	3	0.891
छतीसगढ़	4	0.872
गुजरात	5	0.782
पंजाब	6	0.643
कर्नाटक	7	0.121
आंध्र प्रदेश	8	0.077
झारखंड	9	-0.071
मध्य प्रदेश	10	-0.113
राजस्थान	11	-0.243
महाराष्ट्र	12	-0.360
हरियाणा	13	-0.431
असम	14	-0.459
पश्चिम बंगाल	15	-0.553

ओडिशा	16	-0.910
बिहार	17	-1.343
उत्तर प्रदेश	18	-1.418

छोटे राज्य	रैंक	**PAI 2021** सूचकांक
सिक्किम	1	0.907
गोवा	2	0.748
मिजोरम	3	0.659
हिमाचल प्रदेश	4	0.318
त्रिपुरा	5	-0.009
मेघालय	6	-0.146
अरुणाचल प्रदेश	7	-0.258
नागालैंड	8	-0.317
दिल्ली	9	-0.476
उत्तराखंड	10	-0.643
मणिपुर	11	-0.783

केंद्र शासित प्रदेश	रैंक	**PAI 2021** सूचकांक स्कोर
पुदुचेरी	1	1.345
दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव	5	-0.445
लक्षद्वीप	4	-0.302
जम्मू और कश्मीर	2	0.396
चंडीगढ़	3	-0.298
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	6	-0.696

रिपोर्ट के मुख्य बिंदु:

- पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स सीरीज़ केवल केंद्र सरकार के डेटा स्रोतों के उपयोग पर राज्यों के प्रदर्शन का साक्ष्य आधारित मूल्यांकन है। विभिन्न श्रेणियों में विजेता हैं:
  - बड़े राज्य (लार्ज स्टेट्स) – विजेता – केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना
  - छोटे राज्य (स्माल स्टेट्स) – विजेता – सिक्किम, गोवा और मिजोरम
  - केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) – विजेता– पुदुचेरी, जम्मू और कश्मीर और चंडीगढ़

  बड़े राज्यों की श्रेणी में PAI 2021 की समग्र रैंकिंग में, केरल शीर्ष पर बना हुआ है। इसी तरह, तमिलनाडु ने अपनी दूसरी रैंक बरकरार रखी है। PAI 2020 रैंकिंग से आंध्र प्रदेश की जगह तीसरे स्थान पर तेलंगाना आ गया है। ध्यान दें, यह दिलचस्प है कि तेलंगाना, झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्यों ने अपने मूल राज्यों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया है।
- तेलंगाना, छत्तीसगढ़, झारखंड और गुजरात राज्यों ने समग्र सूचकांक में अच्छा प्रदर्शन किया है, जबकि महाराष्ट्र, असम, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्यों ने पिछले वर्ष की तुलना में रैंकिंग में गिरावट दर्ज की है।
- टॉप और बॉटम परफॉर्मर्स के अलावा, आंध्र प्रदेश, जो पिछले साल तीसरे स्थान पर था, इक्विटी और विकास स्तंभ में भारी गिरावट के कारण **PAI 2021** में **8**वें स्थान पर है। इसी तरह,

कर्नाटक जो चौथे स्थान पर था, वह **3** स्थान गिरकर (इक्विटी स्तंभ में **12**वें से **16**वें स्थान पर फिसलते हुए) **7**वें स्थान पर आ गया है, जबकि स्कोर अभी भी सकारात्मक पक्ष में है, जो राज्य को अपने विकास पथ को पुनः प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान कर रहा है। गुजरात राज्य जो पिछले वर्ष **9**वें स्थान पर था, इस वर्ष **5**वें स्थान पर है। जबकि पश्चिम बंगाल जो पिछले साल 12वें स्थान पर था, 15वें स्थान पर आ गया है, महाराष्ट्र जो पिछले साल 7वें स्थान पर था, वह 12वें स्थान पर आ गया है (इक्विटी स्तंभ में 6वें से 15वें पायदान पर भारी गिरावट के साथ), एक स्पष्ट संकेत है कि राज्य महामारी से उबरने के लिए संघर्ष कर रहा है। यह देखना आश्चर्यजनक तत्वों में से एक रहा कि झारखंड राज्य, जिसने विकास स्तंभ में तीसरे स्थान पर आकर, **15**वें से **9**वें स्थान पर पहुंच कर बहुत अच्छा सुधार किया है।

- जबकि राज्यों ने महामारी का जबरदस्त प्रभाव देखा है, डेल्टा विश्लेषण से पता चलता है कि प्रमुख विकास संकेतकों में साल-दर-साल वृद्धि के संदर्भ में, ओडिशा और नागालैंड ने समग्र रैंकिंग के निचले पायदानों की ओर जगह पाने के बावजूद सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है।
- योजना सूचकांक और **COVID-19** सूचकांक का प्रदर्शन समग्र शासन मॉडल में राज्यों के प्रदर्शन के अनुरूप है। **COVID-19** प्रतिक्रिया सूचकांक में स्पष्ट प्रवृत्ति देखी गई है कि कम प्रति-पूंजी सकल घरेलू उत्पाद वाले राज्यों ने खराब प्रदर्शन दिखाया है और रैंकिंग में सबसे नीचे स्थान प्राप्त किया है, नामतः बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। यह एक उल्लेखनीय अवलोकन है कि इन राज्यों ने महामारी की रोकथाम प्रतिक्रिया के मामले में अच्छा प्रदर्शन किया है, इसका कारण स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे के खस्ता हाल की समस्या की चक्रीय प्रकृति हो सकती है, जिसके कारण **COVID-19** मामलों के सही आंकड़े पता न लग पाना, केस लोड कम होना, और परिणामतः, मृत्यु के मामले कम दर्ज हो पाना।

PAI 2021 का संक्षिप्त सार

PAI 2021, पिछले वर्ष 2020-2021 में राज्यों का शासनात्मक प्रदर्शन कैसा रहा है, इसे समझने के लिए एकीकृत दृष्टिकोण अपनाता है, जिसे COVID-19 द्वारा किए गए व्यवधान की पृष्ठभूमि में देखा गया है। कुछ राज्यों ने अच्छा प्रदर्शन और अन्य ने अपेक्षाकृत खराब प्रदर्शन क्यों किया है, और उनके प्रदर्शन के लिए कौन से कारक जिम्मेदार हैं, इसे समझने के लिए साक्ष्य-आधारित विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

यह केंद्र प्रायोजित कुछ प्रमुख योजनाओं की ओर भी ध्यान आकर्षित करता है और योजना कार्यान्वयन में कमियों की ओर इशारा करता है जिन्हें राज्यों को बेहतर करने के लिए संबोधित करने की आवश्यकता है।

PAI 2021 के कुछ निर्णायक निष्कर्ष इस प्रकार हैं:

1. क्लस्टर विश्लेषण

डेटा का विश्लेषण किया गया और निष्कर्षों ने भारत के राज्यों को तीन समूहों में बांटा जैसा कि नीचे दिखाया गया है:

i. **पहले क्लस्टर** में बड़े राज्यों - केरल, हरियाणा, पंजाब के साथ ही अरुणाचल प्रदेश, दिल्ली, गोवा, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और उत्तराखंड सहित सभी छोटे राज्य शामिल हैं। यह क्लस्टर विकास स्तंभ द्वारा संचालित प्रतीत होता है। उल्लिखित राज्यों ने कृषि क्षेत्र से गैर-कृषि क्षेत्र में संरचनात्मक परिवर्तन के मामले में अच्छा प्रदर्शन किया है। यह भी देखा गया है कि इन राज्यों ने स्वास्थ्य और शिक्षा के परिणामों के मामले में बेहतर प्रदर्शन किया है जिससे उनका प्रदर्शन में सुधार देख गया है।

ii. **दूसरे क्लस्टर** में नौ बड़े राज्य शामिल हैं - आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु और तेलंगाना। यह क्लस्टर स्थिरता स्तंभ (सस्टेनेबिलिटी पिलर) में अपने प्रदर्शन से प्रेरित है। राज्यों ने उत्पन्न ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन की दिशा में सामुदायिक भागीदारी के मामले में बेहतर प्रदर्शन दिखाया है, खाना पकाने के स्वच्छ ईंधन

का उपयोग करने वाले परिवारों का उच्च प्रतिशत, PM10 स्तरों को निम्न बनाए रखने में सहयोगी बन रहा है।

iii. **तीसरे क्लस्टर** में असम, बिहार, झारखंड, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। इस क्लस्टर ने विकास स्तंभ में मध्यम प्रदर्शन और इक्विटी और स्थिरता स्तंभों (सस्टेनेबिलिटी पिलर) में खराब प्रदर्शन दिखाया है। ये राज्य स्वच्छता, पेयजल, खाना पकाने के स्वच्छ ईंधन आदि, बुनियादी ढांचे उपलब्ध कराने के मामले में संघर्ष कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार ने महिलाओं और अल्पसंख्यकों के विरुद्ध होने वाले अपराधों को संबोधित करने के मामले में भी खराब प्रदर्शन किया है, दहेज हत्या और बलात्कार के सर्वाधिक मामले यहाँ दर्ज किए हैं (एनसीआरबी, **2019)**। यह ध्यान देने वाली दिलचस्प बात है कि नीति आयोग द्वारा निर्धारित किए गए **112** जिलों में से **57**, जो कुल आकांक्षी जिलों के **50.8%** हैं, इस क्लस्टर के तहत छह राज्यों के अंतर्गत आते हैं, इसलिए इस क्लस्टर को खराब प्रदर्शनकर्ता के रूप में सुरक्षित तौर पर लेबल किया जा सकता है।

संदर्भ के लिए क्लस्टर मानचित्र देखें

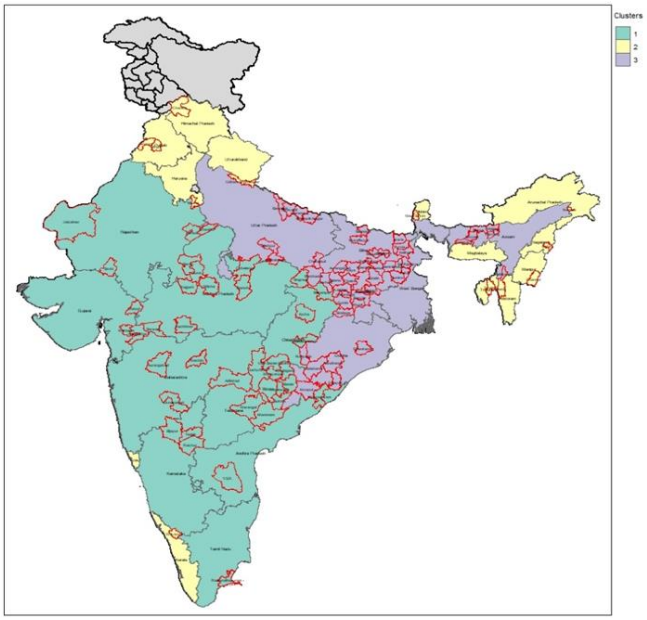

(संयुक्त क्लस्टर मानचित्र)

1. इक्विटी

i. गुजरात बड़े राज्यों की श्रेणी में सबसे ऊपर है, सिक्किम छोटे राज्यों की श्रेणी में सबसे ऊपर है और पुडुचेरी इक्विटी स्तंभ के लिए केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ऊपर है।
ii. उत्तर प्रदेश बड़े राज्यों की श्रेणी में अंतिम स्थान पर है, अरुणाचल प्रदेश छोटे राज्यों की श्रेणी में अंतिम स्थान पर है और दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव संघ शासित प्रदेशों में अंतिम स्थान पर है।
iii. राज्यों का समग्र प्रदर्शन काफी हद तक इक्विटी स्तंभ द्वारा संचालित है, चाहे वे किसी भी श्रेणी में आते हों।
iv. महामारी के अप्रत्यक्ष परिणाम वास्तव में उन राज्यों में अधिक देखे गए जो पहली लहर से गंभीर रूप से प्रभावित हुए थे, यानी कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु आदि (रिपोर्ट में विस्तार से बताया गया है)।

2. विकास

i. विकास स्तंभ (ग्रोथ पिलर) आश्चर्यजनक बढ़ोतरी के साथ इस वर्ष रैंकिंग के मामले में सबसे अस्थिर स्तंभ था।

ii. बड़े राज्यों की श्रेणी में तेलंगाना सबसे ऊपर है, गोवा छोटे राज्यों की श्रेणी में सबसे ऊपर है और पुडुचेरी विकास स्तंभ के लिए केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ऊपर है।

iii. बिहार बड़े राज्यों की श्रेणी में अंतिम स्थान पर है, मेघालय छोटे राज्यों की श्रेणी में अंतिम है और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह संघ शासित प्रदेशों में अंतिम स्थान पर है।

iv. आश्चर्य की बात है कि झारखंड इस रैंकिंग में शीर्ष तीन में है।

v. बड़े राज्यों की श्रेणी में, विकास स्तंभ (ग्रोथ पिलर) में प्रदर्शन, समग्र सूचकांक में प्रदर्शन के लिए महत्वपूर्ण योगदान देता है।

vi. छोटे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में विकास स्तंभ समग्र सूचकांक में प्रदर्शन के लिए मामूली योगदान देता है।

vii. महामारी के भारी प्रभावों का सामना कर रहे राज्यों को विकास के प्रदर्शन में भी डगमगाते देखा गया है।

3. स्थिरता

i. बड़े राज्यों की श्रेणी में केरल सबसे ऊपर है, छोटे राज्यों की श्रेणी में मिजोरम सबसे ऊपर है और स्थिरता स्तंभ के लिए केंद्र शासित प्रदेशों में पुडुचेरी सबसे ऊपर है।

ii. उत्तर प्रदेश बड़े राज्यों की श्रेणी में अंतिम स्थान पर है, दिल्ली छोटे राज्यों की श्रेणी में और लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेशों में अंतिम स्थान पर है।

iii. स्थिरता स्तंभ (सस्टेनेबिलिटी पिलर) बड़े राज्यों के लिए प्रदर्शन का एक चालक है, लेकिन छोटे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदर्शन पर मामूली प्रभाव डालता है।

2. डेल्टा विश्लेषण

डेल्टा विश्लेषण साल-दर-साल सुधार पर राज्यों के प्रदर्शन के आधार पर उनके परिणाम प्रस्तुत करता है। पिछले 5 से 10 वर्षों में 12 प्रमुख विकास संकेतकों के लिए उपलब्ध डेटा के आधार पर रैंकिंग को डेल्टा वैल्यू के रूप में मापा जाता है।

i. बड़े राज्यों की श्रेणी में समग्रतः छत्तीसगढ़ शीर्ष पर रहा जबकि उत्तर प्रदेश अंतिम स्थान पर रहा। छोटे राज्यों की श्रेणी में, नागालैंड शीर्ष पर रहा जबकि मेघालय अंतिम स्थान पर रहा।

ii. इक्विटी के मामले में, छत्तीसगढ़ के बाद ओडिशा और तेलंगाना शीर्ष पर हैं, जबकि झारखंड, असम और उत्तर प्रदेश बड़े राज्यों में सबसे निचले पायदान पर हैं।

iii. छोटे राज्यों के मामले में, दिल्ली शीर्ष पर है, उसके बाद मणिपुर और नागालैंड का स्थान है, जबकि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और गोवा को नीचले पायदानों पर स्थान प्राप्त हुआ है।

iv. विकास स्तंभ में, तेलंगाना, केरल और पश्चिम बंगाल ने डेल्टा में सबसे अधिक वृद्धि दिखाई, जबकि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात बड़े राज्यों में सबसे पीछे रहे।

v. छोटे राज्यों की श्रेणी में, नागालैंड के बाद सिक्किम और त्रिपुरा में डेल्टा में सबसे अधिक वृद्धि हुई है जबकि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और मेघालय सबसे पीछे हैं।

vi. स्थिरता के मामले में, बड़े राज्यों तमिलनाडु, केरल और ओडिशा में, डेल्टा में सबसे बड़ी वृद्धि दिखाई देती है। तेलंगाना, असम और आंध्र प्रदेश डेल्टा रैंकिंग में सबसे नीचे स्थान प्राप्त कर पाए हैं। छोटे राज्यों में, मिजोरम, हिमाचल प्रदेश और त्रिपुरा शीर्ष पर हैं जबकि दिल्ली, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश सबसे नीचे हैं।

vii. 12 प्रमुख विकास संकेतकों के तहत ओडिशा और नागालैंड ने साल-दर-साल सबसे अच्छा सुधार दिखाया है।

4. योजना विश्लेषण

योजना विश्लेषण में, ICDS के अपवाद के साथ, NHM और MDMS के मामले में चार साल के डेटा और मनरेगा और SmSA के मामले में पांच साल के डेटा का उपयोग करते हुए समय-श्रृंखला आधारित मॉडल को अपनाया गया है।

- NHM
  - 60:40 संभाग (डिवीजन) वाले राज्यों में, शीर्ष तीन प्रदर्शन करने वाले केरल, गोवा और तमिलनाडु हैं और निचले तीन पायदानों के प्रदर्शनकर्ता उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार हैं।
  - 90:10 संभाग (डिवीजन) वाले राज्यों में, शीर्ष तीन प्रदर्शन करने वाले राज्य हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और मिजोरम रहे; और, निचले तीन पायदानों पर प्रदर्शन करने वाले मणिपुर, असम और मेघालय हैं।

- ICDS
  - 60:40 संभाग (डिवीजन) वाले राज्यों में, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश शीर्ष तीन प्रदर्शनकर्ता हैं और तमिलनाडु, तेलंगाना और दिल्ली नीचे के तीन प्रदर्शनकर्ताओं के रूप में देखे गए हैं।
  - 90:10 संभाग (डिवीजन) वाले राज्यों में, शीर्ष तीन स्थानों पर प्रदर्शन करने वाले राज्य मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड हैं; और, निचले तीन स्थानों के प्रदर्शनकर्ता जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश हैं।
- MDMS
  - 60:40 संभाग (डिवीजन) वाले राज्यों में, गोवा, पश्चिम बंगाल और दिल्ली शीर्ष तीन प्रदर्शनकर्ता राज्यों के रूप में दिखाई दिए और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और बिहार निचले तीन पायदानों के प्रदर्शनकर्ताओं के रूप में दिखाई दिए हैं।
  - 90:10 संभाग (डिवीजन) वाले राज्यों में, मिजोरम, हिमाचल प्रदेश और त्रिपुरा शीर्ष तीन प्रदर्शनकर्ता रहे और जम्मू और कश्मीर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश प्रदर्शन के आधार पर नीचे के तीन स्थानों पर रहे।
- SmSA
  - पश्चिम बंगाल, बिहार और तमिलनाडु 60:40 संभाग के राज्यों में शीर्ष तीन स्थानों पर थे; जबकि हरियाणा, पंजाब और राजस्थान सबसे नीचे के तीन प्रदर्शनकर्ता के रूप में दिखाई दिए।
  - 90:10 संभाग के राज्यों के संबंध में, मिजोरम, असम और त्रिपुरा शीर्ष तीन प्रदर्शनकर्ता थे और नागालैंड, जम्मू और कश्मीर और उत्तराखंड नीचे के तीन स्थानों पर देखे गए।
- MGNREGS
  - 60:40 संभाग (डिवीजन) वाले राज्यों में, शीर्ष तीन प्रदर्शनकर्ता केरल, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा हैं और नीचे के तीन पायदानों के लिए प्रदर्शनकर्ता मध्य प्रदेश, झारखंड और गोवा रहे हैं।
  - 90:10 संभाग (डिवीजन) वाले राज्यों में, शीर्ष तीन प्रदर्शनकर्ता राज्य मिजोरम, सिक्किम और नागालैंड हैं और निचले तीन निचले तीन पायदानों के प्रदर्शनकर्ता मणिपुर और असम हैं।

5. COVID-19 रेस्पॉन्स इंडेक्स

31 मार्च,2021 से यानी जबसे देश में तक पहला मामला सामने आया था, COVID-19 रेस्पॉन्स इंडेक्स भारतीय राज्यों को महामारी के प्रति उनकी प्रतिक्रिया के आधार पर रैंक करने का एक प्रयास है। यह सूचकांक दो विषयगत क्षेत्रों को समाहित करता है - तैयारी और रोकथाम।

- सूचकांक में शीर्ष 5 पदों में से चार पर दक्षिणी राज्यों का कब्जा है। केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश दोनों स्तंभों में अपने निरंतर प्रदर्शन के कारण शीर्ष 3 स्थानों पर काबिज हैं जबकि कर्नाटक तैयारी के विषय में अपने अच्छे प्रदर्शन के कारण 5 वें स्थान पर है।
- COVID-19 प्रतिक्रिया सूचकांक में देखी गई स्पष्ट प्रवृत्ति उन राज्यों की रैंकिंग है जिनकी आर्थिक और वित्तीय स्थिति अपेक्षाकृत खराब है। ये ऐसे राज्य हैं जिनका प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) कम है, जैसे बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश
- गोवा जो शासन सूचकांक (गवर्नेंस इंडेक्स) में दूसरे स्थान पर है, COVID-19 प्रतिक्रिया सूचकांक में अंतिम स्थान पर है। इसके विपरीत, दिल्ली तैयारी में अपने मजबूत प्रदर्शन के कारण शीर्ष पर है, हालांकि, यह 11 छोटे राज्यों में अपने नियंत्रण संबंधी प्रयासों के कारण 10 वें स्थान पर है।

संपर्क

डॉ. अन्नपूर्णा रविचंदर- अध्यक्ष, नीति अनुबंध और संचार, **PAC**

मोबाइल नं-9880844862

मेल आईडी- annapoorna@pacindia.org